

नियोजन की आवश्यकता

आपदा एक आकस्मिक तथा अनिश्चित चुनौती है, यद्यपि कुछ आपदाओं को रोकना संभव नहीं है जैसे भूकंप, चक्रवात आदि परन्तु उसके प्रभाव का न्यूनीकरण शमन कार्य योजना द्वारा किया जा सकता है। कई मानव जनित आपदाओं को एवं कुछ सीमा तक प्राकृतिक आपदाओं को भी रोका जा सकता है। नियोजन, पूर्व तैयारी, शमन और पूर्वाभ्यास होने पर किसी भी आपदा के प्रभाव को न्यूनतम या कई स्थितियों में नगण्य किया जा सकता है। वर्तमान में आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण और उसे अद्यतन रखे जाने के संबंध में सभी सहमत है, परन्तु प्रश्न यह उठता है, कि क्या राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना पर्याप्त नहीं है। यह क्यों आवश्यक है, कि प्रत्येक जिले की पृथक आपदा प्रबंधन योजना हो, और उसकी क्यों सार्थकता है?

- **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005** – “आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005” के अनुसार भारतवर्ष के प्रत्येक जिले की अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना आवश्यक है।
- **स्थानीय स्थिति**— जब भी किसी क्षेत्र विशेष पर आपदा आती है, तो सर्वप्रथम स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विभाग ही त्वरित अनुक्रिया करते हैं, राज्य और संपूर्ण देश से मद्द आने में समय लगता है, और यदि वे समय पर पहुंच भी जाए तो भी स्थानीय परिस्थितियों और वातावरण से तालमेल बैठाते और उसको समझते—समझते काफी समय निकल जाता है।
- **विशिष्ट क्षेत्र**— प्रत्येक क्षेत्र/जिले की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, प्रशासनिक रूप से वह एक अलग इकाई होता है, और कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित होता है। अतः जिला स्तर पर कार्यवाही करना आसान होता है। ऐसे में जिले की अपनी पृथक आपदा प्रबंधन रणनीति हो, पृथक योजना हो तो कार्य को और सुगम बनाया जा सकता है।

- **इकाई**— इकाई जितनी छोटी होगी, प्रबन्धन भी उतना अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। अतः जिला आपदा प्रबंधन योजना को जितनी जल्दी निर्मित एवं लागू कर दिया जाए उतना ही बेहतर होगा।
- **अभी तक की स्थिति**— जिला मंदसौर में, अद्यतन बहुआयामी एवं अनुकूलतम आपदा प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो पायी थी, यद्यपि समय समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाई गई हैं, परंतु मंदसौर जिले में बाढ़ के अलावा अन्य भी कई प्रकार की आपदाओं की संभावनाएं भी विद्यमान हैं। अधिक अनुकूल, बहुआयामी एवं व्यवस्थित योजना बनाना अति आवश्यक है।
- **पूर्व तैयारी**— आपदा प्रबंधन योजना का एक महत्वपूर्ण चरण होता है— पूर्व तैयारी, अर्थात् किसी भी प्रकार की आपदा के लिए हमारा प्रशासन और समुदाय पूर्णरूपेण तैयार रहें। पूर्व तैयारी में यह शामिल होता है कि किस दल की क्या जिम्मेदारी होगी; किस प्रकार की आपदा आने पर क्या कार्य योजना अपनाई जाएगी, शासन की भूमिका क्या होगी, स्वयंसेवी संस्थाओं की क्या भूमिका होगी और समुदाय की क्या भूमिका होगी। यदि हमारे पास “पूर्व योजना” की एक यथार्थ/सही रूपरेखा हो, एवं समुदाय के विभिन्न वर्गों को उसके अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए, अवास्तविक अभ्यास (Mock drill) करवाए जाएं, तो यह निश्चित है, कि आपदा पर सहज नियंत्रण पाया जा सकता है।
- **विकास तथा आपदा शमन**— आज की आवश्यकता है, कि विकास की अवधारणा में “शमन” को भी शामिल किया जाए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विकास के साथ-साथ विभिन्न आपदाओं से कैसे बचा जाए, और कैसे उनके प्रभावों को कम किया जाये यह जानकारी होना भी एक स्वस्थ विकास का द्योतक है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की निर्माण एवं विनिर्माण संबंधी विकास योजनाओं में आपदा संबंधी “संरचनात्मक” शमन उपायों को प्राथमिकता देते हुए शामिल करना अति आवश्यक है; लोगों में भूकंपरोधी मकान निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति जागरूकता लानी होगी। किसी भी प्रकार के निर्माण परियोजना में यह

आवश्यक होना चाहिए कि आपदा संबंधी संरचनात्मक शमन के तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह ली जाए।

- **तैयार समुदाय—** किसी भी आपदा स्थिति का मुकाबला करने हेतु पूर्व तैयारी हो, संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक शमन ठीक प्रकार से नियोजित हो— समुदाय तैयार हो, तो आपदा की अनुक्रिया कई गुना बेहतर ढंग से एवं न्यूनतम हानि के साथ संपन्न की जा सकती है।
- **योजना एवं कोष सहायता—** शासकीय एवं गैर-शासकीय संस्थाओं के पास “आपदा प्रबंधन” हेतु कोष उपलब्ध है, किंतु इस कोष का बहुत सीमित उपयोग हो रहा है, वास्तव में इस विसंगति का एकमात्र कारण है, अनुकूलतम योजना की अनुपलब्धता। यदि जिले के आपदा प्रबंधन हेतु एक व्यवहारिक एवं अनुकूल योजना हो, एवं उसमें यह स्पष्ट परिलक्षित हो कि किस मद पर कितना व्यय किया जाना है, कितने कोष की आवश्यकता है, तो निश्चय ही आपदाओं का प्रबंधन प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।
- **जागरूकता—** यह सर्व विदित है, कि “आपदा प्रबंधन” के संदर्भ में लोगों का ज्ञान एवं जागरूकता सतही है, चाहे वह आम जनता हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो या अन्य प्राधिकारी हो। ऐसे में यदि सभी अधिकारी प्राधिकारी आदि के साथ मिलकर जब जिला योजना बनाई जाएगी तो आपदा प्रबंधन के संदर्भ में उनका ज्ञान और जागरूकता दोनों विकसित होंगे।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबन्धन संस्थान, भोपाल ने यूनिसेफ (सीबीडीआरएम) के सहयोग से एवं मध्यप्रदेश शासन के सहयोग से मध्यप्रदेश के 10 आपदा के प्रति अति संवेदनशील जिलों के लिए जिला आपदा प्रबन्धन योजना, एवं उन जिलों में भी आपदा के प्रति अति संवेदनशील ग्रामों में, ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने हेतु एक परियोजना प्रारम्भ की है। इस परियोजना अंतर्गत जिला एवं ग्राम स्तर पर कार्यरत विभिन्न प्राधिकृत संस्थाओं को शामिल करते हुए, चयनित जिलों में से

प्रत्येक के 25 अति आपदा प्रभावित ग्रामों में भी ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना को सामुदायिक सहभागिता के आधार पर तैयार किया जाना प्रस्तावित है। इन जिलों में से मंदसौर भी एक चयनित जिला है।

आपदा प्रबन्धन के बदलते प्रतिमान

वर्तमान में आपदाओं के प्रबन्धन में भारत सरकार द्वारा अब केवल “राहत” के विषय को हटाते हुए, एवं एक नये दृष्टिकोण को धारण करते हुए आपदा प्रबन्धन से जुड़े सभी पहलुओं को सम्मिलित कर एक वृहद आपदा प्रबन्धन की कार्य योजना बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस नये दृष्टिकोण में आपदा प्रबन्धन को विकास की एक कड़ी मानते हुए आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु जन सहभागिता सहित कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

आपदा प्रबंधन को विकास की अवधारणा के साथ जोड़ा जा रहा है। विभिन्न स्तरों पर (केन्द्र, राज्य, जिला, तहसील एवं ग्राम) आपदा प्रबंधन हेतु प्रभावी नियोजन एवं जनसहभागिता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन के प्रतिमान अब बदल रहे हैं, जिनके मुख्य बिंदु अग्रांकित हैं –

- विकास एवं आपदा प्रबंधन साथ साथ,
- राहत के अलावा शमन, पूर्व तैयारी एवं अनुक्रिया
- समुदाय आधारित नियोजन,
- ग्राम स्तरीय एवं विभाग स्तरीय नियोजन,
- बहुआयामी एवं बहुस्तरीय नियोजन।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना का उद्देश्य :

आपदा की संभावना या जोखिम को कम करना ही जिला आपदा प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य है। विभिन्न प्राधिकारियों (Stake Holders) के साथ मिलकर बनायी गयी योजना द्वारा, जिसमें विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन हेतु प्रावधान किया गया है, निश्चित ही आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। संक्षेप में जिला आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य निम्नवत है।

1. जिले के प्रमुख खतरों/संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हिकरण जिससे किसी भी आपदा के समय होने वाले नुकसानों को कम किया जा सके।
2. जिले में आपदा के दौरान कार्य करने वाले विभिन्न विभागों एवं अन्य प्राधिकृतों के पास उपलब्ध संसाधन का विश्लेषण करना।
3. जिला स्तर पर आपदाओं से बचने हेतु आवश्यक एवं प्रभावी पूर्व तैयारी; व्यवस्थित, भौतिक संसाधन एवं क्षमतापूर्व मानव संसाधन सुनिश्चित करना।
4. आपदा के प्रभाव में कमी तथा रोकथाम हेतु क्षेत्र विशिष्ट एवं जोखिम के अनुसार कार्य योजना तैयार करना।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना की सीमायें :

किसी भी कार्य योजना की अपनी सीमा होती है, विभिन्न स्थितियों में संकलित/तैयार योजना अपेक्षाओं पर खरी नहीं हो पाती है, तथापि कार्य करने का एक आधार प्रदान करती है। यह कार्य योजना जिले के 25 वर्षों के विभिन्न खतरों, संवेदनशील स्तरों एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सहभागी प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार की गई जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना मंदसौर की सीमायें अग्रांकित हैं—

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के प्रबंधन हेतु निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण का निर्धारण विभिन्न स्तरों पर कार्यरत प्राधिकारी

विभागों/प्रशासन द्वारा आपदाओं का सामना करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है : –

L0 सामान्य समय: इस समय पर जिला प्रशासन/जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा आपदाओं का चिन्हीकरण, संवेदनशील क्षेत्र का चिन्हीकरण, पूर्व तैयारी एवं शमन, अनुक्रिया हेतु दलों का गठन एवं प्रशिक्षण, सामुदायिक जनजागरूकता आदि महत्वपूर्ण चरणों को पूर्ण किया जायेगा।

L1 स्थिति में आपदाओं का सामना जिला स्तर पर किया जा सकेगा। यद्यपि किसी भी सहायता एवं आवश्यकता हेतु राज्य एवं राष्ट्र तैयार रहेंगे।

L2 स्तर की आपदाओं का प्रबंधन बिना राज्य/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग के किया जाना संभव नहीं है।

L3 जिले में एल-3 स्तर की आपदा आने पर बिना राष्ट्र/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग के आपदाओं का सामना करना संभव नहीं है।

2. कुछ विशेष प्रकार के आपदाओं जिनका वर्तमान में हमें कोई पूर्वाभास नहीं हैं, ऐसी किसी अप्रत्याशित आपदा उदाहरणार्थ जैविक आपदाओं के आने पर जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना मन्दसौर पूर्णरूपेण प्रभावी नहीं होगी।

3. जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना निर्माण की प्रक्रिया

जिला मन्दसौर की आपदा प्रबन्धन कार्य योजना का निर्माण निम्नलिखित चरणों को पूरा करते हुए किया गया है।

- जिले के प्रमुख अधिकारियों का आपदा से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर अभिमुखीकरण।
- सभी विभागों के पास उलपब्ध ऑकड़ों का संकलन।
- प्राप्त ऑकड़ों का विश्लेषण

- विशेषज्ञों के साथ सम्पर्क/चर्चा
- प्रथम जिला परामर्श कार्यशाला का आयोजन तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा एवं समूह कार्य के माध्यम से जिलों के प्रमुख खतरों, संवेदनशील क्षेत्रों, संसाधनों का चिन्हीकरण।
- प्राप्त तथ्यों का संकलन।
- द्वितीय जिला परामर्श कार्यशाला का आयोजन तथा जिले में उपलब्ध आपदा प्रबन्धन तथा जिले में उपलब्ध आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं आपदा प्रबन्धन की रणनीति, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्य, जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष की स्थापना, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की भूमिका, इत्यादि, चिह्नित आपदाओं के रोकथाम एवं शमन हेतु जिले की तैयारी, मानव संसाधन उपकरण, आपदा अनुक्रिया हेतु दलों का गठन एवं भूमिका इत्यादि पर चर्चा एवं समूह कार्य के माध्यम से उपरोक्त तथ्यों की पहचान एवं तैयारी।
- प्राप्त तथ्यों का संकलन।
- तृतीय जिला परामर्श कार्यशाला का आयोजन तथा प्रथम एवं द्वितीय कार्यशाला से प्राप्त तथ्यों के आधार पर एवं अनुक्रिया हेतु जिले में चिन्हित खतरों के रोकथाम प्रभावी शमन एवं अनुक्रिया हेतु विभिन्न गतिविधियों, बजट तथा वार्षिक कार्य योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- तैयार जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना स्वीकृति हेतु राज्य प्राधिकरण को प्रेषित की जायेगी तथा स्वीकृति उपरान्त योजना को लागू कर दिया जायेगा।

जिला मन्दसौर



आधारभूत जानकारियाँ	
गठन	1 नवम्बर 1956
भौगोलिक क्षेत्रफल	5517 वर्ग किलोमीटर
भौगोलिक स्थिति	$23^{\circ}46'$ से $24^{\circ}45'$ उत्तरीय अक्षांश तथा $74^{\circ}44'$ से $75^{\circ}54'$ पूर्व देशांतर
जनसंख्या	1183724 (जनगणना 2001)
जनसंख्या घनत्व	214 प्रति वर्ग किमी. (जनगणना 2001)
पुरुष	605119 (जनगणना 2001)
महिला	578605 (जनगणना 2001)
जनसंख्या वृद्धि दर (दशकीय)	23.67 (जनगणना 2001)
लिंगानुपात	956 महिलायें प्रति 1000 पुरुष (जनगणना 2001)
कुल साक्षरता दर	70.31 प्रतिशत (जनगणना 2001)
पुरुष साक्षरता दर	85.2 प्रतिशत (जनगणना 2001)
स्त्री साक्षरता दर	54.7 प्रतिशत (जनगणना 2001)
जन्म दर	30 प्रति 1000
मृत्यु दर	11 प्रति 1000
शिशु मृत्यु दर	88 प्रति 1000 जीवित जन्म
कृषि भूमि	321497
वन क्षेत्र	36814 हेक्टेयर
ऊँचाई (समुद्र तल से)	453 मीटर
जिले की सीमाएं	जिले के पश्चिम एवं उत्तर में राजस्थान का जिला चित्तौड़गढ़, जिले के उत्तर में राजस्थान का भीलवाड़ा और पूर्वोत्तर में कोटा एवं झालावाड़, तथा जिला के दक्षिण में रतलाम जिला स्थित है।
तापमान	45 डिग्री सेल्सियस (मई) अधिकतम

	6 डिग्री सेल्सियस (जनवरी) न्युनतम
औसत वर्षा	786.6 मिमी०
विद्युतकीय ग्राम	899
प्रमुख खनिज पदार्थ	खड़िया, मोरम, रेत, गेरु, लालमिट्टी
प्रमुख व्यवसाय	कृषि, पशुपालन
प्रमुख फसलें	गेहूं, सोयाबीन, मूगफली, तिलहन, अफीम, चना, धान, ज्वार, धनिया एवं अन्य मसाले

जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

मन्दसौर जिले का गठन मध्यप्रदेश के गठन के साथ ही 1 नवम्बर 1956 में हुआ था। मन्दसौर जिला सिवना नदी के किनारे बसा है। इतिहास में दशपुर के नाम से प्रसिद्ध मन्दसौर में विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपति नाथ मंदिर शिवना नदी तट पर स्थित है। प्राचीन काल में मन्दसौर राज्य पर महाराजा यशोधर्मन का शासन होकर उनके द्वारा हूणों पर विजय प्राप्त की गई थी। विजय के उपलक्ष्य में पाषाण विजय स्तंभ तैयार कर विजय गाथा का वर्णन किया गया। यह विश्व प्रसिद्ध शिलालेख मन्दसौर के निकट ग्राम सोंधनी में स्थित है। मन्दसौर जिले में अनेक ऐतिहासिक दार्शनिक स्थल हैं जिनमें से हिंगलाज गढ़ का किला धर्मराजेश्वर की पाण्डु गुफा, भानपुरा की छतरी, लधुना का जलमहल, एवं सितामोह (जिसे छोटीकाशी के नाम से जाना जाता है), विश्व प्रसिद्ध इतिहास पुस्तकालय—नटनागर शोध संस्था आदि स्थित हैं।

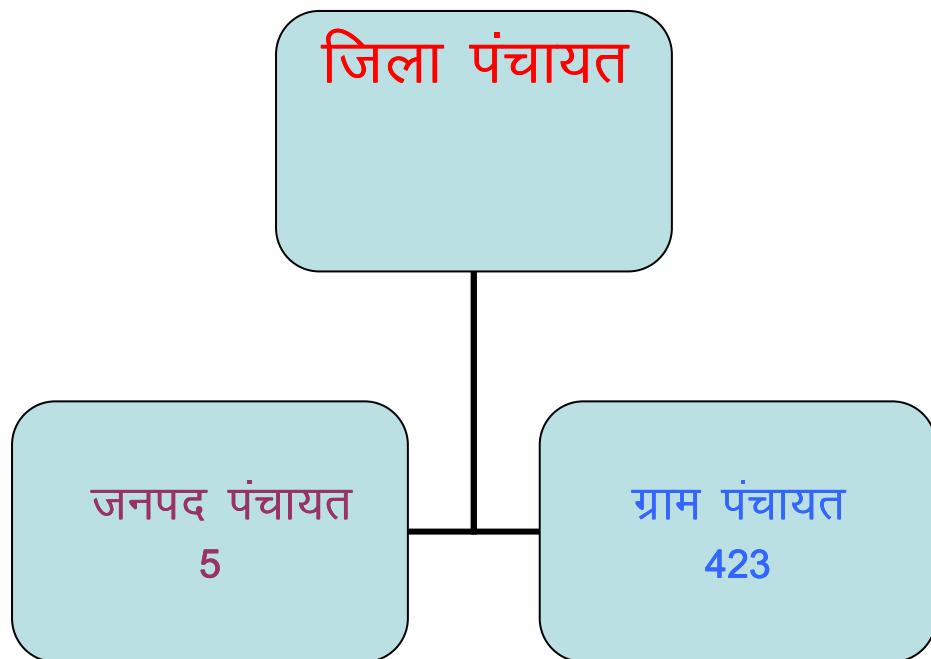
प्रशासनिक इकाइयों का विवरण

प्रशासनिक तंत्र	
संभाग	उज्जैन
जिला	मन्दसौर
अनुभाग	04
तहसील	1 मन्दसौर 2 भानपुरा 3 गरोठ 4 मल्हारगढ़ 5 सीतामऊ 6 सुवासरा 7 दलौदा 8 शामगढ़
विकासखण्ड	1 मन्दसौर 2 गरोठ 3 सीतामऊ 4 मल्हारगढ़ 5 भानपुरा
नगरपालिका	01
विधान सभा क्षेत्र	04
जिला पंचायत	01
नगर पंचायत	08
जनपद पंचायत	05
ग्राम पंचायत	440
राजस्व ग्राम	941
आबाद ग्राम	899
वीरान ग्राम	42

जिला मन्दसौर की तहसीलें



स्थानीय निकाय



भौगोलिक संरचना

स्थिति : मंदसौर जिला स्थिति के रूप में मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थिति है, परन्तु यह पश्चिमी संभाग क्षेत्र उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। यह $23^{\circ}45'50''$ पूर्व उत्तर से $25^{\circ}2'55''$ उत्तर अक्षांश के बीच में पड़ता है एवं देशांतर रेखांश में $74^{\circ}42'30''$ पूरब एवं $75^{\circ}50'20''$ पूरब रेखाओं के बीच स्थित है।

सीमाएँ : जिले की राजस्थान के चार जिलों से घिरी हुई है जो कि पश्चिम में चितौड़गढ़, उत्तर में भीलबाड़ा, उत्तर-पूर्व में घोटा एवं पूरब में झालाबाड़ से घिरा हुआ है वहीं पर मध्यप्रदेश की रतलाम जिला दक्षिण से लगा हुआ है।

क्षेत्रफल : मंदसौर जिला मध्यप्रदेश के सामान्य जिलों के बराबर क्षेत्रफल में है। यह उत्तर से दक्षिण 142 कि.मी. एवं पूर्व से पश्चिम 124 कि.मी. क्षेत्र में फैला हआ है।

वार्षिक वर्षा : यहाँ पर वार्षिक वर्षा लगभग 786.6 मि.मी. होती है।

जिले के प्रमुख बांधों का विवरण: मन्दसौर जिले में तीन बड़े बांध हैं। इनमें से गाँधी सागर सबसे बड़ा है। गाँधी सागर बांध जिला मुख्यालय से 168 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यह बांध चम्बल नदी के ऊपर निर्मित किया गया है। इस बांध के निर्माण का सुभारम्भ 07 मार्च 1954 को भारत के तातकालिक प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस बांध में विद्युत उत्पादन का कार्य भी किया जाता है। 23 मेगावाट क्षमता की कुल पाँच टरबाइने लगी हैं, जिनसे कुल 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तैयार बिजली मध्य प्रदेश के साथ-साथ राजस्थान के कुछ जिलों को भी प्रदान की जाती है।

जलवायु एवं तापमान

जिले की जलवायु समशीतोष्ण है। सर्दियाँ प्राया नवम्बर से जनवरी तक चलती हैं जबकि तापमान औसत 06 डिग्री सेलसियस से 25 डिग्री सेलसियस के बीच रहता है। फरवरी माह में सर्दी का प्रभाव कम हो जाता है। मार्च से जून तक गर्मियों का मौसम रहता है; गर्मियों में तापमान 30° सेलसियस से 45° सेलसियस के बीच रहता है।

जिले में पिछले पाँच वर्षों में औषत वर्षा (मि०मी० में):

क्र.	वर्ष	वर्षा
1	2004–05	421
2	2005–06	657
3	2006–07	1409
4	2007–08	759

स्रोत: जिला सांख्यकीय पुस्तिका

आर्द्धता

वर्षा ऋतु को छोड़ जब कि आर्द्धता अधिक रहती है, जिले का वातावरण सामान्यतः शुष्क रहता है। वर्ष का शुष्कतम भाग ग्रीष्मकाल होता है, जब आपेक्षित आर्द्धता 20 प्रतिशत से भी कम होती है।

मेघाच्छन्नता

वर्षा ऋतु को छोड़ जब आकश में बहुत बादल छाए होते हैं या आकाश मेघाच्छन्न होता है, आकाश स्वच्छ होता है या उसमें हल्के बादल छाये होते हैं।

जिला मन्दसौर में जनसंख्या एवं अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े

समान्य जानकारी जिला मन्दसौर

तालिका क्र0 1.1						
क्र0	विकास खण्ड	भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग कि0मी0	आबाद ग्राम	ग्राम पंचायम	जनपद पंचायत	जिला पंचायत
1	भानपुरा	1039	86	45	01	00
2	गरोठ	1130	195	91	01	00
3	मल्हारगढ	806	168	78	01	00
4	मन्दसौर	1266	223	119	01	01
5	सीतामऊ	1276	234	108	01	00

तालिका क्र0 1.2						
क्र0	विकास खण्ड	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्के	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	दशकीय वृद्धि
1	मन्दसौर	03	82	316432	396919	25.42
2	भानपुरा	01	23	105917	132722	25.30
3	गरोठ	02	45	179869	224325	24.70
4	मल्हारगढ	02	43	154348	185079	19.90
5	सीतामऊ	03	62	200303	244679	22.15

तालिका क्र० 1.3

क्र०	विकास खण्ड	अन०जा०	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	अ०ज०जा०	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1	भानपुरा	20965	15.80	6615	4.98
2	गरोठ	44239	19.72	2394	1.07
3	मल्हारगढ	35908	19.40	7665	4.14
4	मन्दसौर	59403	14.97	17449	4.4
5	सीतामऊ	51747	21.15	3403	1.39

तालिका क्र० 1.4

क्र०	विकास खण्ड	कुल साक्षरों की संख्या 2001	साक्षरता प्रतिशत
1	भानपुरा	71956	65.34
2	गरोठ	115837	62.43
3	मल्हारगढ	117426	75.24
4	मन्दसौर	246222	73.70
5	सीतामऊ	147745	72.50

शैक्षणिक संस्थाओं का विवरण

क्र.	विकास खण्ड	प्राथमिक शालाएं	माध्यमिक शालाएं	हाईस्कूल	हायर सेकेण्ड्री	महाविद्यालय	व्यवसायिक	आश्रम शालाएं
1	मन्दसौर	496	308	48	34	02	08	00
2	भानपुरा	212	91	17	10	01	00	00
3	गरोठ	334	144	22	13	01	01	00
4	मल्हारगढ़	298	168	20	09	00	01	00
5	सीतामऊ	378	196	28	10	00	00	00
योग		1718	907	135	76	04	10	00

स्रोत : जिला सांख्यिकीय पुस्तिका 2008

चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र :

क्र.	विकास खण्ड	एलोपैथिक चिकित्सालय	प्राथ.स्वा. केन्द्र	उपस्वा. केन्द्र	आयुर्वेदिक / होम्यो / यूनानी	उपलब्ध शैयाएं	
						एलोपैथिक	अन्य पद्धति
1	मन्दसौर	01	07	42	12	292	30
2	भानपुरा	01	12	19	04	51	00
3	गरोठ	01	13	34	07	96	00
4	मल्हारगढ़	00	08	35	05	42	00
5	सीतामऊ	00	07	38	09	68	00
योग		03	47	168	37	549	30

स्रोत : जिला सांख्यिकीय पुस्तिका 2008

उपलब्ध चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / कर्मचारी

क्र.	विकास खण्ड का नाम	चिकित्सा अधिकारी		संक्रामक रोग निवारणार्थ कर्मचारी	स्वास्थ्य निरीक्षक	नर्स	कम्पाण्डर	अन्य
		एलोपैथी	अन्य पद्धति					
1	मन्दसौर	32	10	237	00	103	02	00
2	भानपुरा	06	00	89	00	40	01	00
3	गरोठ	08	02	159	00	65	02	00
4	मल्हारगढ़	11	02	133	00	71	01	00
5	सीतामऊ	07	03	132	00	68	02	00
योग		64	17	750	00	347	08	00

स्रोत : जिला सांख्यकीय पुस्तिका 2008

पशु चिकित्सालय एवं औषधालयों का विवरण

क्र०	विकास खण्ड	चिकित्सालय	औषधालय
1	भानपुरा	01	05
2	गरोठ	02	08
3	मल्हारगढ़	01	08
4	मन्दसौर	01	06
5	सीतामऊ	01	06
योग		06	33

सार्वजनिक वितरण प्रणाली उचित मूल्य की दुकानों का विवरण

क्र0	विकासखण्ड	शहरी	ग्रामीण	कुल
1	मन्दसौर	26	93	119
2	भानपुरा	04	28	32
3	गरोठ	05	62	67
4	मल्हारगढ़	06	67	73
5	सीतामऊ	03	86	89
कुल योग		44	336	380

यातायात व्यवस्था – रेल सड़क वायु तथा जल

रेल :

जिले से रेल मार्ग दिल्ली मुम्बई गुजरता है जिसके प्रमुख रेल्वे स्टेशन शामगढ़, सुवासरा तथा गरोठ हैं। एक अन्य रेल मार्ग रतलाम अजमेर है जो जिले में पचनारा, दलोदा, मन्दसौर, पिपलिया मंडी तथा मल्हारगढ़ होकर गुजरता है।

सड़क :

जिले से तीन प्रमुख राज्य मार्ग गुजरते हैं, राज्य मार्ग 79 बोतलगंज से मन्दसौर एवं फतेहगढ़, बोतलगंज से चलदू नीमच सीमा तक जाती है। राज्य मार्ग 31 प्रतापगढ़ से चौमेला, मन्दसौर, सीतामऊ होकर गुजरती है। राज्य मार्ग 31 ए झालावाड रोड राजस्थान सीमा से नीमच तक गुजरती है।

वायु :

जिले में कोई हवाई अड्डा नहीं है। निकटवर्ती हवाई अड्डा इन्दौर में है जो मन्दसौर से लगभग 200 किमी दूर है।

जलमार्ग :

जिला मन्दसौर में बडे जलमार्ग की कोई संभावना नहीं है परंतु छोटे-छोटे जलमार्ग का उपयोग लोगों द्वारा किया जाता है जिले में बड़े बाधों एवं चम्बल नदी होने के कारण एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिये लोग छोटी एवं बड़ी नाव का उपयोग करते हैं। जिसमें कई बार नाव दुर्घटनायें भी हुई हैं।

संचार व्यवस्था

क्र0	तहसील	प्रधान डाक घर	प्राथमिक/उप डाक घर	शाखा कार्यलय
1	भानपुरा	00	03	21
2	गरोठ	00	02	36
3	मल्हारगढ़	00	04	35
4	मन्दसौर	01	10	55
5	सीतामऊ	00	04	28
6	सुवासरा	00	01	18
7	दलौदा			
8	शामगढ़			
योग		01	24	203

स्रोत : जिला सांख्यिकीय पुस्तिका 2008, "नवगठित तहसीलों का विवरण अप्राप्त।"